सेवामें, दिनांकः–

चेयरमैन साहब,
टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया
जवाहर लाल नेहरू मार्ग
नई दिल्ली–110002

विषयः– टैरिफ पर परामर्श पत्र संख्या 10/2019 दिनांक 16 अगस्त 2019 से संबंधित।

महोदय,

परामर्श पत्र संख्या 10/2019 दिनांक 16 अगस्त 2019 द्वारा मांगे गए सुझाव के क्रम में उल्लेख है कि जैसा कि आप जानते हैं कि केबल टी.वी. आम उपभोक्ताओं के लिए सूचना स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने का एकमात्र सस्ता साधन था जो आठवें टैरिफ के लागू होने के पश्चात् कुछ ब्राडकास्टर्स ने उसे आम उपभोक्ताओं के लिए केबल टी.वी. महंगा व टैरिफ का फायदा लेना कठिन कर दिया।

महोदय, किसी बुके/पैकेज में शामिल चैनल्स् के कुल मूल्य पर बुके/पैकेज के मूल्य पर छूट की अधिकतम सीमा (कैप) न होने और जिसके चलते कुछ ब्राडकास्टर्स द्वारा अनुचित तरीके से नजायज फायदा उठाया गया है उसे देखते हुए इस अधिकतम छूट (15% Cap) को 15% से घटाकर 10% कर देना चाहिए/उचित होगा जिससे उपभोक्ताओं को अगर पैकेज की जगह अलग–अलग स्वतंत्र रूप से चैनल्स् लेने हो तो उन्हें चुनने में सहूलियत मिलेगी।

महोदय, अगर छूट की अधिकतम सीमा लागू हुई होती तो उपभोक्ता अपने मनोरंजन बजट में खर्च करने वाली रकम में ज्यादा ब्राडकास्टर्स के चैनल्स् ले सकता था।

महोदय, ब्राडकास्टर्स के द्वारा DPO [MSO+LCO] को पे–चैनल्स पर दिया जाने वाली 20% छूट बहुत ही कम है इस 20% में से MSO व LCO दोनों को आपस में अपना–अपना हिस्सा बाटना है, जिसमें LCO को बहुत ही कम नाम मात्र का राजस्व मिल रहा है, उदाहरण के तौर पर अगर किसी पै–चैनल मूल्य 10 रूपये है, उसमें कुल DPO Fee 20% यानि 2 रूपये और इसमें LCO मार्जिन 20% का 45% यानि 90 पैसे मात्र जो बिल्कुल अनुचित एवं अमान्य है।

महोदय, अगर आपके 15 मार्च 2016 के The Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) interconnection (Digital addressable cable Television systems) (Seventh Amendment regulation, 2016 (no. 3 of 2016) के Clause 12 Revenue Settlement between the MSO and LCO related rights and obligations के Sub Clause 12.1 (d) के अनुसार The Charges collected from the Subscription of channels and bouquet of channels other than those specified under clause (a) shall be shared in the ratio of 65:35 between the MSO and the LCO respectively के अनुसार भी अगर गणना करें तोः–

चैनल का मूल्य = 10.00 रूपये

MSO Margin 65% = 6.50/-

LCO Margin 35% = 3.50/-

यही नहीं उक्त Seventh amendment के अनुसार MSO उसे मिलने वाले 65% हिस्से में से है ब्राडकास्टर को उसके 10 रूपये के चैनल का हिस्सा देता।

अतः **महोदय** बेहद अफसोस के साथ यह प्रश्न विचारणीय है, कि इस आठवें टैरिफ संशोधन के बाद LCO को 10 रूपये कीमत के चैनल में से मात्र 90 पैसे मिल पा रहे हैं जबकि पहले उसे उसी 10 रूपये के चैनल में से 3.50 रूपये मिलते थे। इस प्रकार मात्र 90 पैसे पर LCO किस प्रकार कार्य करें।

अतः **महोदय** 20% की सीमा को बढ़ाना अति आवश्यक है। यह इस प्रकार हो कि LCO को चैनल (बुके के मूल्य का कम से कम 35% राजस्व प्राप्त हो। अर्थात् DPO Fee 60% (45:15, LCO : MSO) हो जिसमें से 45% LCO व 15% MSO को मिलना चाहिए।

महोदय वर्तमान में NCF 130 रूपये NCF पर वर्तमान में जो नियम है वह उचित है फिलहाल उनमें बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें MSO व LCO की रेवेन्यू हिस्सेदारी 10:90 के अनुपात में होनी चाहिए जिसमें 10% MSO व 90% LCO को, क्योंकि MSO को कैरिज Fee, प्लेसमेन्ट Fee, लेंडिग पेज एग्रीमेन्ट आदि और भी अन्य के द्वारा आय होती है जबकि LCO मात्र NCF के हिस्सेदारी पर ही निर्भर है और उसे अपने सारे खर्च और अपग्रेडेशन इसी में से करनी पड़ रही है।

महोदय, सबसे महत्वपूर्ण विषय पर प्राधिकरण का ध्यान ही नहीं गया है जबकि इस विषय पर ध्यान पूर्व में ही दिया जाना आवश्यक था जब आठवें टैरिफ के अनुसार कोई भी PAY/FTA चैनल सभी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म के लिए समान रूप से PAY/FTA रहेगा लागू है, लेकिन महोदय, तो फिर कुछ ब्राडकास्टर्स अपने PAY चैनल्स् को DTH जैसे DD-Free Dish से न तो पै–चैनल्स् का मूल्य ले रहे है, बल्कि, पैसे देकर (स्लाट लेकर) अपने पै–चैनल्स् का मूल्य ले रहे हैं बल्कि पैसे देकर (स्लाट लेकर) अपने पै–चैनल्स् को चला कर नियमों को खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं और प्राधिकरण ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की है।

महोदय, जो ब्राडकास्टर्स DTH जैसे DD Free Dish पर अपने चैनल्स् प्रसारित कर रहे हैं उन्हें आदेशित किया जाना चाहिए कि वे उन चैनल्स् को FTA घोषित करें अन्यथा DTH जैसे DD Free Dish पर उन चैनल्स् का प्रसारण तुरन्त प्रभाव से बन्द करें जिससे नियमों का उल्लंघन बन्द हो।

महोदय, यहां पर यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि हमारी आपत्ति DD Free Dish पर PAY चैनल्स् फी उपलब्ध होने से नहीं है बल्कि हमारी आपत्ति उन ब्राडकास्टर्स को बाकि तमाम् प्लेटफार्मस् पर भी उन चैनल्स् को Free to Air नहीं करने से है।

FIRST OPTION: As mentioned above because 15% Cap is actually spam of the NTO by which the hole NTO look birth and to maintain the said NTO alive than TRAI must inject the SOLE of the NTO (15% Cap) into again, any other Try & Error Experiments will result the industry dies for Sure.

ALTERNATE OPTION: Most suitable ALTERNATE OPTION available is to RE-IMPLEMENT the ''CAS'' REGULATIONS which was suggested by the than COST MANAGERS of the TRAI and approved by the than I & B MINISTRY and surprisingly without and SPECIFIC-OPPOSITION the said ''CAS'' REGULATION WAS DROPPED.

THANKS & REGARDS

Name of LCO's Firm: VIPIN CABLE NETWORK

Name of LCO : PRAKASH GUJRATI

Address : 1813, BILALA HOUSE, HALDIYON KA RASTA,

JOHARI BAZAR, JAIPUR, 302003

PH. : 9829022510